नई शिक्षा नीती २०२० :– मुद्दे तथा चुनौतियॉ

डॉ. बाबुदास साधुराम दमाहे
श्रीमती सुग्रता वंजारी महिला
महाविद्यालय , वडोदा ता–कामठी
जि–नागपुर
babudas.damahe@gmail.com
8605955517

प्रस्तावना

समय के साथ बदलाव यह प्रकृति का नियम है। गुजरा हुआ कल की आवश्यकताओं के आधार पर बनाये गये नियम नीति तथा योजनाएँ,उन्हे पुरा करने में सक्षम होते है। परंतु जैसे–जैसे समाज व समाज के साथ–साथ देश और दुनिया का विकास होता है उसी प्रकार परिस्थिति बदलती है। और परिस्थितिनुरुप आवश्यकताये , और उस आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये नई योजनायें बनाये जाते है । नई योजनाओं को पुरा करने के लिए नई तकनिकि की जरुरत होती है। और नई तकनिकि को समझने व सिखने के लिए नई शिक्षा नीती की आवश्यकता होती है। इसी तर्ज पर भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से आवश्यकतानुसार शिक्षा नीती में बदलाव कर विभिन्न कालखण्ड में अलग–अलग शिक्षा नीती तैयार की गई।

भारतीय सविधान के चौथे भाग में लिखित नीती निदे ाक तत्वों में कहा गया है, कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चो को अनिर्वाय और नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । १९४८ में डॉ. राधाकृश्णन की अध्यक्षता मे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा –प्रणाली को व्यवस्थित करने का कामशुरु हो गया ।

१९५२ में लक्ष्मनस्वामी मुदलीयार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा १९६४ में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर १९६८ में शिक्षा नीती पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबध्द,चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक–युवतियो को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया।

मई १९८६ में स्वतंत्र भारत में पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीती लागू की गई, जो अब चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीती की समीक्षा के लिए १९९० में आचार्य राममुर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा १९९३ में प्रो. यश्पाल समिती का गठन किया गया ।

नई शिक्षा नीती २०२०

नई शिक्षा के नीती २०२० जिसे वर्तमान भारत सरकार द्वारा ३४ वर्ष बाद २९ जुलाई २०२० को घोि ात किया गया । सन १९८६ के शिक्षा नीती के बाद भारत की शि़क्षा नीती में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीती अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समीती की रिपोर्ट पर आधारित है।

नई शिक्षा नीती २०२० यह वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया । इस नीती के अंतर्गत अध्यापन क्रिया में क्षेत्रिय भाषा पर बल दिया गया है साथ ही व्यकितगत गुण कौशल,

व्यक्तिमत्व विकास जिसमे कि,छात्र सिर्फ नौकरशाही के लिये नही,अपितु स्वंय रोजगार के लिए अपने आपको तैयार करे।

संशोधन पध्दति

संबंधित शोध निबंध को पुरा करने के लिए विवरणात्मक संशोधन पध्दति का उपयोग किया गया है ।

स्रोत

संबंधीत निबंध को पुर्णरूप देने हेतु जानकारी विभिन्न पुस्तके, मासिके, दैनिक समाचार पत्र तथा संकेत स्थान का उपयोग किया गया है ।

शोध निबंध के उददेश

- नई शिक्षा नीती का उच्च शिक्षण क्षेत्र में प्रभाव का पता लगाना।
- नई शिक्षा नीती का मुल्याकंन करना ।
- नई शिक्षा नीती को प्रभावित करनेवाले घटको का पता लगाना ।
- नई शिक्षा नीती के मे ं आनेवाले समस्याओं का पता लगाना ।
- नई शिक्षा नीती के पुरा करने हेतु आर्थिक घटक का पता लगाना ।

परिकल्पना

- नई शिक्षा नीतीयह उच्च शिक्षा क्षेत्र में धनात्मक प्रभाव डालता है।
- नई शिक्षा नीती यह भवि य में अच्छा परिणाम देगा ।
- नई शिक्षा नीती को सामाजिक तथा राजकिय घटक प्रभावित करते है।
- नई शिक्षा नीती को पुरा करने में अनेक समस्याये आने की संभावना है ।
- नई शिक्षा नीती को आर्थिक घटक प्रभावित करता है।

नई शिक्षा नीती २०२०

नई शिक्षा नीती २०२०की कुछ प्रमुख मुददे निम्न प्रकार से है ।

शिक्षा का अतंराष्ट्रीयकरण, संस्थागत सहयोग तथा छात्र और संकाय गतिशिलता के माध्यम से किया जायेगा शीर्ष विश्व रैंकिग वाले विश्वविघालयो को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

मुलभुत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्राथमिकता पर एक रा ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा । कक्षा १–३ में प्रारभिक भा ाा और गणित पर विशे ा ध्यान देने की जरुरत है। NEP २०२० का लक्ष्य यह सुनिशित करना है कि कक्षा ३ तक प्रत्येक विद्यार्थि को २०२५ तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए । मस्ति क विकास और अधिगम सिध्दांतो के आधार पर स्कुली शिक्षा के लिए एक नई विकासयुक्त पाठयचर्या और ैक्षणिक संरचना ५+३+३+४ डिजाइन पर विकसित कि गई है।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर

कम से कम कक्षा तक लेकिन कक्षा आठ और उसमे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलु भाषा/मातृभाषा/स्थानिक भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी ।

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा मे वर्ष २०३५ तक सफल नामाकन अनुपात बढाकर कमसे कम ५० प्रतिशत तक पहुचाना

समग्र बहुविषयक शिक्षा नीती

इस नीती में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रो के लिए एकीकृत और श्रमसाध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु–अनु ासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसके कल्पनाशील और लचीली पाठय संरचना अध्ययन का रचनात्मक संयोजन व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश/निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

अभिशासन

प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षनिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित है जिसके प्रत्येक उच्चशिक्षा संस्थान मे एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा ।

विनियमन

उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्व समावेशी (अम्ब्रेला) निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन,वित्तपो ाण,प्रत्यायन और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाईयो की स्थापना की जाएगी। हित के टराव को समाप्त करने के लिए व वित्तीय सत्यनि ठा और सार्वजनिक प्रकल्प सुनिश्चित करने हेतु विनिमयन होगा जिसके निरिक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म प्रकटीकरण एक मानक होगा । विनियामक नियम प्रौघोगिकी के माध्यम से फैसले सविनियमन का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानको के विपरित संचालित उच्चतर शिक्षण संस्था नों के विरूध दंडात्मक कार्यवाई करने की शक्तिया प्राप्त होगी । सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानो पर नियमन प्रत्यायन फंडिंग व शैक्षणिक मानको संबंधी मापदंड समान रूप से लागू होगा ।

मुक्त और दुरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा जिसके माध्यम से सफल नामांकन अनुपाते को ५० प्रतिशत तक बढाने में महत्वपुर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाईन कोर्स एव डिजिटल रिपॉजिटरी अनुसंधान के लिए वित्तपो ाण , बेहतर छात्र सेवाओ , मूक की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि उपायो को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जायेगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमो के समान हो ।

व्यावसायिक शिक्षा

सभी प्रकार के व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी । एकल तकनिकी स्वास्थ्य विज्ञान विधि और कृषि विश्व विद्यालय अथवा अन्य विषयों के विश्वविद्यालय बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे । वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी । नई शिक्षा नीती का उददेश वर्ष २०२५ तक ५० प्रतिशत छात्रो को वोकेशनल शिक्षा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

अनुसंधान और न वाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी।

शिक्षा में प्रोद्योगिकी अधिगम मुल्यांकन योजना और प्रशासन को बढाने के लिए प्रोद्योगिकी के उपयोग व विचारो के नि:शुल्क आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय प्रदान किया जायेगा । कक्षा प्रक्रियाओ में सुधार शिक्षको के व्यवसायिक विकास का समर्थन,वंचित समुहो के लिए

शैक्षणिक पहुँच बढाने और शैक्षणिक योजना,प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभि स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा ।

नई शिक्षा नीति २०२० के उद्देश

- शिक्षा कि पहुँच,समानता,गुणवत्ता,वहनीय,शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- छात्रों के आवश्यक कौशलो एवं ज्ञान से परिपुर्ण करना और विज्ञान, टेक्नालॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश का ज्ञान आधारित सुपर पावर के रुप में स्थापित करना है।
- शिक्षा कि नीति को छात्रो में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना।
- भाषाई बाध्यताओं को दुर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।

उच्च शिक्षा आयोग

- भारतिय उच्च शिक्षा आयोग को संपुर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रुप में किया जायेगा। इतमे मेडिकल और कानुनी शिक्षा को सामिल नही किया जाएगा।
- वर्ष २०४० तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानो का उद्देश अपने आप को बहू–विषयक संस्थानों के रुप में स्थापित करना होगा।
- वर्ष २०३० तक प्रत्येक जिले मैं या उसके समीप कम–से–कम एक बड़ा बहू–विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों स्थापित किया जायेगा।
- के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शितापुर्ण निष्पादन के लिये चार विकायों का निर्धारण किया गया हैं।
- HECI के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शितापुर्ण निष्पादन के लिये चार विकायों का निर्धारण किया गया है।
- विनिमय हेतु– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद।
- मानाक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद।
- वित्त–पोषण –उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग परिषद।
- प्रत्यायन– राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद।

अनुसंधान

- नई शिक्षा नीि तमे एम. फिल (M.PHIL) को समाप्त किया जायेगा।
- पी. एच. डी के लिए ४ वर्षीय ग्रेजुएशन फिर एम.ए. उसके बाद एम.फिल कि अनिवार्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- रा ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) राष्ट्र में गुणवत्तपुर्ण अनुसंधान को सही रुप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियत्रंण रखने के लिए का गठन।

निष्कर्ष

शोध सबंध के उपरोक्त विभिन्न पहलूओं का अवलोकन करने पर निम्न प्रकार से निष्कर्ष सामने आया है।

- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन कि बात कही गई है सराहनिय है परंतु उसे वास्ताविक रुप देने के लिए विभिन्न शासकिय तथा शैक्षणिक संस्थानों में एक सुत्रता लाना अति आवश्यक है। यदि हम विभिन्न संस्थाओं के मध्य तालमेल नही बैठा पाए तो उपरोक्त उद्देश को प्राप्त करना एक सपना ही रह जाएगा।
- नई शिक्षा निती यह स्कुलि स्तर से तो उच्चतर शिक्षा स्तर तक छात्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों को मुल्यांकन पध्दति योग्य रुप से तभि संभव है जब नई शिक्षा निति में संकायों के आवश्यक विभागों का तालमेल अर्थात विभिन्न कौशल्य विकास में सहायक तंत्र तथा विभाग एकत्रित हो। यदि कौशल्य विकास से संबंधित कुछ घटक का अभाव है, या प्रशिक्षत शिक्षकों का अभाव है तो हम उपरोक्त लक्ष्य को हासिल नही कर सकेंगे, क्योकि वर्तमान में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (B.Ed, D.Ed) में सिखाये जानेवाले अध्यापन पध्दति या सिलेबस उससे अलग है जो किं नई शिक्षा निती के अतंर्गत दिया गया है
- नई शिक्षा निती को सामाजिक राजनितिक, वित्तीय तथा भौगोलिक ऐसे विभिन्न घटक प्रभावित करते है। नई शिक्षा निति को पुरा करने में जब तक उपरोक्त घटक सहयोगी नही होंगे तब तक NEP 2020 का उद्देश पुरा नही हो पायेगा। नई शिक्षा निती यह केंद्र सरकार द्वारा है। उठाया गया एक सराहनिय कदम है, परंतु जब तक देश के राज्य सरकारे अपने–अपने राज्यों में सहयोग नही करेंगे तब तक उसे वास्तविक स्वरुप प्राप्त नही हो सकेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए खर्च अधिक लगेगा जिसे वहन करना सभी पालकों के लिए संभव नही है। जब तक कि खर्च, सरकार द्वारा नही किया जाता। नई शिक्षा निती के तहत देश के प्रत्येक जिल्हा स्तर पर एक बहु–विषयक संस्थान शुरु करने का निर्णय लिया गया है, परंतु यह तभी संभव है, जब देश के ऐसे भोगोलिक क्षेत्र का विकास किया जाय,जहा अभि तक विकास की कोई निव ही नही रखी गई है।
- नई शिक्षा निती को पुरा होने में प्रमुख समस्याये विचारों का है। भारत जैसे देश में नविनिकरण का अक्सर विरोध किया गया है। क्यों कि नविनिकरण द्वारा होने वाले फायदे को न देखते हुये,उसके उपर उंगली उठानेवालो की कमी नही होती। इसका प्रमुख कारण लोगों में तथ्य को समझने से ज्यादा, राजनिती करने की प्रवृत्ती अधिक पायी जाती है । और जब तक देश में राजकिय गलियारों में पक्ष और विपक्ष एकमत नही होंगे तब तक कोई भी योजना का सफल होना एक मिल का पत्थर ही साबित होंगा।
- नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए आर्थिक घट महत्वपुर्ण है। जिसके लिए NEP2020 में विनिमय को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। शिक्षा क्षेत्र में निजि विनियोग बढ़ाकर हम वित्तपो ाण कर सकते है। परंतु यह तभि योग्य होगा जब सरकार के नियंत्रण में हो, यदि नही तो शिक्षा का निजिकरण होने में देर नही लगेगा, और शिक्षा का निजिकरण हो जायेगा तो सामाजिक परिस्थित बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और हमारा उद्देश, देश के सभी वर्ग को शिक्षत

करने का सपना, एक सपना ही रह जायेगा। नीति के अंतर्गत देश के कुल GDP का ६ प्रतिशत योगदान देने की बात कही गई है, वह सराहनिसय है परंतु तभी लाभकारी है जब वह जमिन स्तर पर दिखे।

सुचना

- नई शिक्षा नीति का अमल में लाने हेतु शिक्षण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संस्थाओं को विश्वास में लिया जाना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुल्याँकन पध्दति में तालमेल बिठाना आवश्यक है। तथा मुल्यांकन पध्दति में पारदशिता लाना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति का उद्देश पुरा करने के लिए विभिन्न घटकों जैसे: राजकिय, सामाजिक घटकों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है।
- नई शिक्षा नीति को योग्य रुप सें संचालित करने हेंतु संबधित पक्ष तथा विभागों को विश्वास में लेना आवश्यक हैं।
- नई शिक्षा नीति को क्रियात्मक करने हेतु योग्य वित्त व्यवस्था और उसका योग्य उपयोग आवश्यक है।

संदर्भ

- नई शिक्षा नीति पर निबंध www.hindikiduniya.com
- https://motivational.page/new-education-policy-in-hindi
- नई शिक्षा नीति पर निबंध 2020httsp://hindijankari-innew-shiksha0neeti-nibandh-essay-education=policy
- नई शिक्षा नीति की मुख्य विशे ाताएं www.jansatta.com
- New National Education Policy 2020 PDF : नई शिक्षा नीति क्या है? का बढ़ावा नाम-----hindi.careeindia.com
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 hindi.rajras.in/nayi-rajras
- विश्व शब्दकोष , वर्तमानपत्र नवभारत, लोकमत समाचार